नई दिल्ली, रविवार
2 फरवरी 2020
मूल्य ₹ 5.00
पृष्ठ 22+4+6+4=36

दैनिक जागरण

www.jagran.com

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

ग्रेटर नोएडा

आम बजट : निवेशकों ने जताई निराशा, बिल्डर संतुष्ट

ग्रेटर नोएडा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 आम बजट लोक सभा में पेश किया। आम बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया, लेकिन विभिन्न बिल्डर की परियोजनाओं में निवेश करने वाले खरीदारों ने बजट को निराशाजनक बताया है। वहीं बिल्डरों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट पर संतुष्टि दिखाते हुए मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। दरअसल, आम बजट से खरीदार काफी उम्मीद लगाए बैठे थे। लाखों खरीदार फ्लैट पर कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र में दोबारा भाजपा की सरकार आने के बाद खरीदारों को काफी उम्मीद बंधी थी। उन्हें लग रहा था कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखा सकती है, लेकिन आम बजट से उनकी यह उम्मीद टूट गई।

खरीदारों की प्रतिक्रिया

बजट फ्लैट खरीदारों के लिए निराशाजनक रहा। उम्मीद थी कि घर खरीदारों को कुछ न कुछ सहुलियत दी जाएगी। फ्लैट खरीदारों को न तो फ्लैट मिल रहा है और न ही बैंक की भारी भरकम किस्त में छूट, हां नए फ्लैट खरीदारों को एक लाख रुपये की सब्सिडी जरूर मिल रही है। -**अन्नू खान**, नेफोमा अध्यक्ष

आम बजट से काफी उम्मीद थी । लेकिन बजट से फ्लैट खरीदारों के लिए कोई राहत नहीं मिली है। बजट से लोग अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। फ्लैट खरीदारों की सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। -**विवेक रमन**, निवेशक

बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं में फंसे फ्लैट खरीदारों को उनका आशियाना मिल सके। अधर में फंसी बिल्डर परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए स्ट्रेस फंड की बजट में कोई चर्चा तक नहीं हुई। फ्लैट खरीदारों के साथ मध्यमवर्ग के लिए भी कुछ खास बजट नहीं है। -**नवल सिंह**, निवेशक

बिल्डरों की प्रतिक्रिया

सरकार के कई सकारात्मक कदमों के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक बढ़िया बजट है। मूल स्लैब श्रेणी के करदाताओं के आयकर दर में कमी के साथ उनके हाथों में आय का बड़ा हिस्सा होगा। घर खरीदने का यह सबसे बेहतर समय है। यह बजट पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे भारत के रियल्टी क्षेत्र को एक व्यापक विकास प्रदान करेगा।
-**मनप्रीत सिंह चड्ढा**, प्रमोटर वेव समूह

बजट रियल एस्टेट के नजरिए से मिश्रित है। हालांकि कम दरों और कई छूट के साथ आयकर व्यवस्था का सरलीकरण एक और वर्ष तक किफायती आवासों के लिए घोषित उपायों का विस्तार इस क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा निराश है।
-**मनोज गौड़, एमडी**, गौर समूह व चेयरमैन अफोर्डेबल हाउसिंग कमिटी, क्रेडाई

बजट से रियल एस्टेट को सीधे तौर पर कुछ नहीं मिला है, लेकिन ऐसी कई घोषणाएं है जो अप्रत्यक्ष रूप से इस सेक्टर की मदद करेंगी। इसका फायदा अफोर्डेबल हाउसिंग टैक्स हॉलिडे से मिलेगा। यदि कोई डेवलपर अपने उत्पाद को सर्किल दर से कम दर पर बेचता है तो टैक्स को वापस लेने से डेवलपर्स और खरीदारों को फायदा होगा।-**धीरज जैन**, महागुन समूह

एक वर्ष तक 45 लाख रुपये तक के किफायती आवास पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का विस्तार सही दिशा में एक कदम है। अफोर्डेबल हाउसिंग पर एक वर्ष के लिए कैपिटल गेन का विस्तार भी सही कदम है। मुंबई-दिल्ली कॉरिडोर को जोड़ना समय की जरूरत है। जिसे वित्त मंत्री ने बताने की कोशिश की है।-**हरविंदर सिंह सिक्का**, एमडी, सिक्का समूह

शिक्षा जगत के प्रतिक्रिया

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार पीपीपी मॉडल लागू करना चाह रही है। इसका फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब में छूट आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद है।
-**रमन बत्रा**, कार्यकारी उपाध्यक्ष एनआईईटी कॉलेज

स्किल डेवलपमेंट व नई टेक्नालॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट पर विशेष ध्यान दिया है। आने वाले समय में यह देश की प्रगति में अहम योगदान निभाएंगे। **ध्रुव गलगोटिया**, सीईओ गलगोटिया विवि

सरकार एक तरफ देशी की बात करती है दूसरी तरफ शिक्षा में विदेशी निवेश चाह रही है। शिक्षा व स्वास्थ्य में पीपीपी मॉडल शुरू कर रही है। गाइडलाइन तैयार होने के बाद स्थिति साफ होगी।
-**पीके गुप्ता**, चांसलर शारदा विवि